

# भारत की आन्तरिक सुरक्षा : गम्भीर चुनौती

## India's Internal Security: A Serious Challenge

Paper Submission: 15/11/2020, Date of Acceptance: 25/11/2020, Date of Publication: 26/11/2020



### रुदल कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर,  
राजनीति विज्ञान विभाग,  
किसान स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय, रकसा, रतसर,  
बलिया, उत्तर प्रदेश, भारत

### सारांश

आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आन्तरिक सुरक्षा का मुद्दा। अब आन्तरिक सुरक्षा एक नए प्रकार की जंग लड़ने जैसा है। आन्तरिक सुरक्षा के साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीक जुड़ गई है। इसके चलते आन्तरिक सुरक्षा और ज्यादा संवेदनशील, जटिल और कठिन हो गई है। अब परमाणु आतंकवाद की बात भी शुरू हो गयी है। हो सकता है, किसी आतंकवादी संगठन के हाथ परमाणु हथियार लग जाएं तो वे आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकते हैं। पारम्परिक युद्ध की बजाय अब छद्म युद्ध के रूप में आंतरिक सुरक्षा हमारे लिए बड़ी चुनौती बन गयी है। धीरे-धीरे यह आंतरिक सुरक्षा के सीमित दायरे से आगे की बात होती जा रही है। अब जबकि आंतरिक सुरक्षा ज्यादा संवेदनशील मोड़ पर आ गई है, आतंकवाद उससे जुड़ गया है। आज हमें लगता है कि सबसे बड़ा आन्तरिक खतरा हमारे देश में रह रहे कुछ ऐसे मुसलमानों से है, जो रोज नये षड्यन्त्र भारत माँ के विभाजन के लिए रच रहे हैं।

Today the issue of internal security has become very important for the country. Now internal security is like fighting a new type of war. Modern science and technology have been combined with internal security. Due to this, internal security has become more sensitive, complex and difficult. Now talk of nuclear terrorism has also started. Maybe, if a terrorist organization gets nuclear weapons, then they can become a challenge for internal security. Internal security has become a big challenge for us now in the form of proxy war instead of traditional war. Gradually, it is becoming beyond the limited scope of internal security. Now that internal security has taken a more sensitive turn, terrorism has joined it. Today we feel that the biggest internal danger is from some such Muslims living in our country, who are plotting new conspiracies every day for the partition of Mother India.

**मुख्य शब्द :** साम्प्रदायिकता, हिन्दू व मुस्लिम, आतंकवादियों, चुनौती।

Communalism, Hindu and Muslim, terrorists, challenge.

### प्रस्तावना

देश तीन ओर से सीमा विवाद युक्त राष्ट्रों से घिरा है। इनमें दो परमाणु-शस्त्र सम्पन्न हैं। सीमापार जेहादी आतंकवाद, म्यांमार में बढ़ती अशान्ति, व नेपाल आदि अन्य दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में पाक व चीन की बढ़ती छद्म गतिविधियां, लंका में फैला संघातक गृह-युद्ध व उसके कारण वहाँ विदेशी सैन्य विशेषज्ञों की बढ़ती उपस्थिति आदि भी हमारे रक्षा सरोकार हैं। म्यांमार, थाईलैण्ड व मलेशिया सीमाओं के मध्य-क्षेत्र एवं पाक-ईरान-अफगान सीमाओं के मध्यवर्ती क्षेत्र आज नशीले पदार्थों के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक केन्द्र बन चुके हैं। इन सुनहरे त्रिकोण व सुनहरे क्रीसेंट के रूप में जाने जाते दोनों क्षेत्रों के बीच स्थित हमारा देश, वहाँ से यूरोप व अमेरिका तक, तस्करी के लिए राजमार्ग-सा बनता जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाराणसी, मुम्बई, हैदराबाद व गोधरा जैसे आतंककारी आक्रमण संगठित वोट बैंक के लोभ में कथित सेक्यूलरवादियों का इनमें लिप्त तत्वों के हाथ का खिलौना बनते चले जाना भी रक्षा-क्षेत्र के लिए एक विकट चुनौती है।

### अध्ययन का उद्देश्य

एक देश की सुरक्षा के दो पहलू होते हैं, आन्तरिक और वाह्य। आन्तरिक सुरक्षा से तात्पर्य एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से हैं। पारम्परिक युद्ध की बजाय अब छद्म युद्ध के रूप में आन्तरिक सुरक्षा हमारे लिए बड़ी चुनौती बन गई है। जहाँ तक आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न है भारत में लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत हैं। भारतीय सेनायें गैर राजनीतिक हैं, फिर भी

साम्प्रदायिकता तथा हिन्दू व मुस्लिम सम्बन्धों की समस्याओं में राष्ट्रीय एकीकरण में समस्याएँ उत्पन्न की हुई हैं। अयोध्या, मुम्बई, गुजरात, गोरखपुर, जम्मू कश्मीर इत्यादि की तात्कालिक घटनाओं से देश का राजनीतिक वातावरण दूषित हुआ है। भारत की आन्तरिक सुरक्षा को भ्रष्टाचार और अनुत्तरदायी राजनीति से खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस राजनीतिक वातावरण को भारत की असंतुलित जनसंख्या वृद्धि, गैर तरीके से दूसरे देशों से भारत में प्रवेश कर रहे रोहंग्या मुसलमान आने वाले समय में भारत के लिए आन्तरिक सुरक्षा को खतरा दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भारत-नेपाल सीमावर्ती जिलों में भारत तथा नेपाल की सीमाओं पर मदरसों की संख्या में पिछले पांच से सात वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह मदरसे भारतीय सीमाओं पर सक्रिय होकर सामरिक दृष्टि से भारत की आन्तरिक सुरक्षा को गलत तरह से प्रभावित कर रहा है। अतः प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारत की आन्तरिक सुरक्षा को कौन-कौन सी शक्तियाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं उसे रोकना तथा भारत की आन्तरिक सुरक्षा को कैसे बेहतर और मजबूत बनाया जाय, से है।

#### भारत की आन्तरिक सुरक्षा

स्मरण रहे कि संसद पर 6 आतंकवादियों ने हमला किया था, अक्षरधाम में 10-12 और रघुनाथ मन्दिर में दो आतंकवादी घुस गए थे, वाराणसी के संकटमोचन मन्दिर तथा हैदराबाद की मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज के समय बम धमाकों में 13 लोग मारे गये। पाकिस्तान-भारत के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में भी बम विस्फोट हुआ था। आज के आतंकवादी ज्यादा प्रशिक्षित हैं, उनका मनोबल बहुत ऊँचा है और उनके पास अत्याधुनिक संवेदनशील हथियार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी कमान और नियंत्रण व संचार प्रणाली। इस समय दुनिया में इतने संवेदनशील संचार उपकरण हैं, कि व्यक्ति कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी व्यक्ति से ई-मेल, फोन के जरिए बात कर सकता है। उपग्रह संचार प्रणाली, मोबाईल फोन से अपनी बात कुछ ही सेकेंडों में कहीं से कहीं पहुंचाई जा सकती है। आतंकवादियों का यह संजाल बहुत शक्तिशाली है। आने वाले समय में यह और अधिक संवेदनशील हो जाएगा। इसे रोक पाना इतना आसान नहीं होगा।

न्यूयार्क में 11 दिसम्बर को हुआ हमला इसका प्रमाण है। किसी एक कमान केन्द्र से उस पूरे अभियान को संचालित करना इस बात का भी प्रमाण है। उस पूरी आतंकवादी कार्रवाई का केन्द्र अफगानिस्तान में या ओसामा बिन लादेन की जेब में हो सकता था। लेकिन सत्य यह है कि यह पूरे विश्व में फैला हुआ है। भारत में संसद, अक्षरधाम और फिर रघुनाथ मन्दिर पर हमले आतंकवादियों की सुसंगठित संचार प्रणाली का नमूना है। संसद पर हमले का कमान केन्द्र कहाँ था, यह पता नहीं लगा है। हो सकता है पाकिस्तान इसका केन्द्र हो या फिर भारत का कोई शहर। दूसरी चुनौती है संवेदनशील हथियार और उपकरण। बम के साथ टाइमर लगा दीजिए। वह निर्धारित घंटों और दिनों के बाद फटेगा। संवेदनशील विस्फोटक भी आ गए हैं। जिनका विस्फोटक

सूँघने वाले उपकरण भी पता नहीं लगा पाते। सुरक्षा बलों के लिए उन्हें ढूँढ पाना बेहद मुश्किल काम है और सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवादी को पहचानना। इसके साथ एक और गम्भीर चुनौती है। तेजी से बढ़ता मजहबी उन्नाद का सबसे बड़ा प्रमाण है मानव बम। भारत में अभी इनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मानव बम आतंकवाद का भविष्य है। ये मानव बम कहीं से भी आ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चलता-फिरता जिंदा बम हो सकता है। उसका मनोबल इतना ऊँचा है कि वह मरने तक को तैयार है और फिर विस्फोटक और यंत्र इतने संवेदनशील है कि अगर किसी आदमी ने उन्हें अपने शरीर पर लगा रखा है, तो उनका पता लगा पाना तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि उसके कपड़े न उतारे जाएं। कई विस्फोट तो खोज यंत्रों को झुठला सकते हैं, जैसे रिमोट नियंत्रित उपकरण आदि हैं। जैसे एयरो मॉडल शो में छोटे-छोटे जहाज जैसे उड़ाए जाते हैं, वैसे अगर कोई एयरो मॉडल में विस्फोटक लगाकर उड़ा दें, तो वह बहुत घातक हो सकता है। अगर परमाणु हथियार और रासायनिक हथियार इन आतंकवादियों के हाथ में आ जाएं जो पूरी दुनिया इस बारे में चिंतित होगी। यदि कोई जल वितरण केन्द्र में रसायन मिला दे तो उसका असर क्या होगा? ये आतंकवादी हरकतें आतंकवादी सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। ऐसी गुप्तचर सूचनाएं हैं कि आतंकवादी नेपाल के अतिरिक्त समुद्री सीमा से भी भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते रहे हैं। नयी तकनीकों का भी आतंक फैलाने में प्रयोग किया जा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमें आन्तरिक सुरक्षा के लिए रणनीति बनानी होगी।

रणनीति के रूप में भारत के नागरिकों को पहचान-पत्र बनाने की बात हो रही है लेकिन सीमा पर घुसपैठ तो रोकनी ही होगी। घुसपैठिए हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस पर बहुत जल्दी और गहराई से ध्यान देना होगा। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों, राजस्थान, उत्तर-पूर्वी राज्यों की सीमाओं से लोग आकर भारतीय इलाकों में बस जाते हैं। ये घुसपैठिए आतंकवादियों की पैदावार के लिए उपजाऊ जमीन का काम कर रहे हैं और इन्हें पहचान पाना मुश्किल है। हमारे अड़ोस-पड़ोस में भी कोई घुसपैठिया हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है।

सरकार ने राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने की बात कही है। गुप्तचर संस्थाएं आतंकवाद विरोधी मुहिम की रीढ़ है। यह तो नहीं कहना चाहिए कि वे सक्षम नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि उनका काम कठिन है विभिन्न गुप्तचर संस्थाओं के बीच तालमेल की कमी दिखाई देती है। उनका प्रयास संयुक्त रूप से होना चाहिए। अधिकांश गुप्तचर संस्थाएं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आती हैं। इनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर.एन.ए.डब्ल्यू, सेना का गुप्तचर विभाग आदि शामिल हैं। इन गुप्तचर संस्थाओं के अत्याधुनिक संवेदनशील यंत्रों से सुसज्जित करना आवश्यक है ताकि गुप्त संकेतों को पकड़ सकें। स्मरण रहे कि मुशर्रफ और नवाज शरीफ की बातचीत को हमारी गुप्तचर संस्थाओं ने रिकार्ड कर लिया था। वह अगले दिन भारतीय अखबारों में आ गई थी। यह हमारी गुप्तचर

संस्थाओं की क्षमता का प्रदर्शन था। यह काम उन्होंने अवरोधक उपकरण (इंटरसेप्शन इक्विपमेंट) के माध्यम से किया। हमें ऐसे उपकरण हासिल करने और उनका आविष्कार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इजराईल, अमेरीका आदि के पास ऐसे संवेदनशील उपकरण हैं जो किसी भी प्रसारण की तरंगों को आसानी से पकड़ सकता है। दूसरा हमें बहुत सारे रात्रि दृश्यता उपकरण (नाइट विजन इक्विपमेंट्स) जैसे-अंधेरे में देख सकते वाले विशेष प्रकार के चश्में, दूरबीनें, लेजर दृश्यता आदि चाहिए।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर व बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के कार्य को प्रारम्भ किया है। 13 राज्यों में इस दिशा में काम शुरू हुआ है। सभी राज्यों ने इस पर सहमति, व्यक्त की है कि देश में अवैध रूप से रहे विदेशियों की पहचान करने में राष्ट्रीय नागरिकता और बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचानपत्र विशेष उपयोगी सिद्ध होंगे। सभी राज्य इस दिशा में प्रारम्भिक दौर में यह योजना जम्मू-कश्मीर, गुजरात, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, अरुणांचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, गोवा, पांडिचेरी और दिल्ली आदि में शुरू की गयी है।

आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से गुप्तचर संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आतंकवादियों और संगठित अपराधों में लिप्त लोगों के बारे में गुप्त सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त कार्यबल गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। यह कार्यबल विभिन्न गुप्तचर संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के आदान-प्रदान व समन्वय का काम करेगा। बिखरी सूचनाओं के आधार पर कोई भी सफल सुनियोजित कार्रवाई कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए आतंकवादियों से निबटने के लिए केन्द्र और राज्यों की गुप्तचर संस्थाएं मिलकर काम करें। पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने और इसके गुप्तचरों को पहचानकर खत्म करने के लिए निचले स्तर से सूचनाएं एकत्रित करनी होंगी। जिसमें पुलिस थानों और राज्य गुप्तचर विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।

आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भारत सरकार द्वारा विदेशों में बसे भारतवासियों को दी गई दोहरी नागरिकता की घोषणा में भी सामने आया। काफी विचार-विमर्श के बाद भारत सरकार ने कुछ ही देशों में बसे भारतवासियों को दोहरी नागरिकता की सुविधा देने की घोषणा की है। भारत सरकार ने स्पष्ट भी किया है कि आंतरिक सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए सिर्फ उन्हीं देशों में बसे भारतवासियों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी, जिनसे हमारी सिर्फ आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ध्यातव्य है कि अमेरिका और ब्रिटेन प्रत्येक वर्ष परिस्थितियों के अनुसार अपने आन्तरिक सुरक्षा सिद्धान्त को संशोधित करते हैं और उन

नीतियों पर एक सार्वजनिक चर्चा आयोजित की जाती है, लेकिन इस मोर्चे पर भारत ने अपने दोनों महत्वपूर्ण साझेदारों से कुछ नहीं सीखा है, जबकि हम जानते हैं कि भारत में यह समस्या और भी जटिल है।

### निष्कर्ष

आंतरिक सुरक्षा की दिशा में सरकार की विंता और उसके द्वारा की जा रही पहल प्रशंसनीय है जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति की स्थापना आदि। लेकिन सरकार की इस पहल का सार्थक परिणाम तभी मिल पाएगा जब देश का हर नागरिक देश के एक चौकीदार की तरह काम करे, राजनीतिक नेतृत्व उसे सही राह दिखाए, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए किन्हीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शह न दें, मीडिया एक चौकन्ने और समझदार रखवाले की तरह काम करें। एक-दूसरे से आगे निकल जाने के लिए सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता आंतरिक सुरक्षा के लिए कितनी घातक हो सकती है, इसका उदाहरण गुजरात में देखने को मिला। लेकिन उस चुनौती का सामना कैसे होगा जहां धार्मिक अन्धानुकरण में मुस्लिम समुदाय पोलियो ड्राप भी नहीं पिलाना चाहता तथा परिवार नियोजन भी नहीं अपनाना चाहता। परिणाम स्वरूप, मुस्लिम जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है जो आगामी समय में सामाजिक-धार्मिक आधार पर नवीन चुनौतियों को जन्म देगी।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ब्रिगेडियर, अरुण बाजपेयी, नवम्बर 2002. "भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का परिदृश्य" राष्ट्रधर्म।
2. शर्मा, डॉ० भगवती प्रसाद, नवम्बर 2002, "रक्षा क्षेत्र की चुनौतियाँ प्रभावी प्रतिकार आवश्यक" राष्ट्ररक्षा विशेषांक
3. गुरुमुर्ति, श्री एस०, 02 नवम्बर 2003, "देश के लिए नई चुनौती" पान्जन्य।
4. नेहरू, अरुण, 04 नवम्बर 2005, "खतरे में आन्तरिक सुरक्षा" दैनिक जागरण।
5. कुमार, संजीव, 27 नवम्बर 2005, "खतरे से घिरा देश" पान्जन्य।
6. पुंज, बलवीर, 06 जून 2006, "माओवादियों के हाथों में नेपाल" दैनिक जागरण।
7. गुप्ता, संजय, "आन्तरिक सुरक्षा की उपेक्षा" दैनिक जागरण।
8. ब्रिगेडियर, अरुण बाजपेयी, नवम्बर 2002. "भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का परिदृश्य" राष्ट्रधर्म।
9. रावत, ज्ञानेन्द्र, 7 जनवरी 2003, "बांग्लादेशी घुसपैटिए से बेहाल देश" दैनिक जागरण।
10. वर्मन, भूमिधर, 6 अगस्त 2006 "पहले घुसपैठ अब जमीन पर कब्जा" पान्जन्य।